



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 7, 2014/आश्विन 15, 1936

No. 515]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2014/ASVINA 15, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 707(अ).— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जम्मू और कश्मीर निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियम, 1997 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- (1) इन नियमों को जम्मू और कश्मीर निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) इन नियमों को 1 जनवरी, 2014 से लागू माना जाएगा।
- जम्मू और कश्मीर निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियम, 1997 के नियम 1 के उप नियम 3 में "2013" के लिए "2015" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 15012/1/2014-स्था.(घ)]

ममता कुंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम, भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 10 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 208(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

- सा.का.नि. 826(अ) दिनांक 27 दिसम्बर, 1999;
- सा.का.नि. 919(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2001;
- सा.का.नि. 879(अ) दिनांक 10 नवम्बर, 2003;
- सा.का.नि. 707(अ) दिनांक 06 दिसम्बर, 2005;
- सा.का.नि. 761(अ) दिनांक 07 दिसम्बर, 2007;
- सा.का.नि. 839(अ) दिनांक 23 नवम्बर, 2009 एवं
- सा.का.नि. 915(अ) दिनांक 30 दिसम्बर, 2011

स्पष्टीपरक टिप्पणी

केंद्र सरकार ने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक सामान्यतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य में निवास करने वाले सभी निवासियों के लिए 31 दिसम्बर, 2013 से अगले दो वर्षों तक आयु संबंधी छूट देने का निर्णय लिया है।

2. स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2014

G.S.R. 707(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and posts) Rules, 1997, namely:-

1. (1) These rules may be called the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and posts) Amendment Rules, 2014.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of January, 2014.
2. In the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and posts) Rules, 1997, in rule 1, in sub-rule(3), for the figures “2013”, the figures “2015” shall be substituted.

[F.No.15012/1/2014-Estt(D)]

MAMTA KUNDRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 208(E) dated the 10th April, 1997 and subsequently amended *vide*:-

1. G.S.R. 826(E) dated the 27th December, 1999;
2. G.S.R. 919(E) dated the 22nd December, 2001;
3. G.S.R. 879(E) dated the 10th November, 2003;
4. G.S.R. 707(E) dated the 6th December, 2005;
5. G.S.R. 761 (E) dated the 7th December, 2007;
6. G.S.R. 839 (E) dated the 23rd November, 2009; and
7. G.S.R. 915(E) dated the 30th December, 2011.

EXPLANATORY NOTE

The Central Government has decided to extend the age relaxation to all persons who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st day of January, 1980 to the 31st day of December, 1989 for a further period of two years beyond 31st December, 2013.

2. It is clarified that nobody's interest will be adversely affected by the retrospective effect being given to the rules.